



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, १ फरवरी, १९९७/१२ माघ, १९१८

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, २७ जनवरी, १९९७

संख्या ई० एक्स० एन०-एफ०(१३) १/९६(१).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, १९६८ (१९६८ का २४) की धारा ४२ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिशत की दर से विक्रय कर उद्ग्रहित करने और (i) विद्यमान औद्योगिक इकाईयों और (ii) नई औद्योगिक इकाईयों जो कि औद्योगिक ब्लॉक "ए" "बी" और "सी" के किसी प्रवर्ग में स्थित हों, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: १-१२/७३-ई० एण्ड.बी.-III, तारीख २५-९-९२ द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में १-१०-१९९२ को प्रकाशित और हिमाचल प्रदेश सरकार आवकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या ई० एक्स० एन० एफ०(१३) १/९६(Vi), तारीख २७-१-१९९७ द्वारा यथा संशोधित नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाईयों से अन्यथा जो कि १-१०-१९९६ या इसके पश्चात यथास्थिति हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम या हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (शडयूल कर्मागल

बैंक) द्वारा ग्रहण किए गए हों और तत्पश्चात् नए प्रबन्ध मण्डल/प्रमोटरों/कम्पनी (जिसके प्रमोटर/निदेशक/प्रबन्धक सभी नये हों) को विक्रय कर दी गई हो, सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से 3 वर्ष (36 मास) की अवधि के लिए उनके द्वारा माल के विनिर्माण और विक्रय के सम्बन्ध में उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन उद्ग्राह्य बिक्री कर के शेष भाग के संदाय से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट भी प्रदान करते हैं:—

- (i) इस प्रकार ग्रहण की गई और बेची गई इकाई के आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित सभी पूर्व दायित्वों से मुक्त कर दी गई हों और इस प्रभाव का “बेबाकी प्रमाण पत्र” समुचित निर्धारण प्राधिकारी से प्राप्त कर लिया हों ;
- (ii) औद्योगिक इकाई जिसमें प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक समुचित निर्धारण प्राधिकारी के पास हिमाचल प्रदेश सरकार आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा तारीख 12-2-1992 राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 1-12/73-ई एण्ड टी-III, तारीख में 7-2-1992 में विहित प्रारूप आर.एम.-II में एक प्रमाण पत्र दायर कर दी हों ;
- (iii) 1. प्रतिशत की दर से विक्रय कर की रियायती दरों की सुविधा (लाभ) केवल उन औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध होगी जो:—
 - (क) ऐसी औद्योगिक इकाई के ग्रहण और विक्रय के पश्चात्, समुचित निर्धारण प्राधिकारी के पास हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 (1968 का 24) के अधीन, व्याहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हों ;
 - (ख) हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 (1968 का 24) के उपबन्धों, तदधीन बनाये गए नियमों और जारी की गई अधिसूचनाओं का अनुपालन करती हों ;
 - (ग) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश या उद्योग विभाग के जिला उद्योग केन्द्र के महा-प्रबन्धक से क्रय की गई इकाई के सम्बन्ध में उद्योग विभाग को संदेय किसी देय के बारे में “बेबाकी प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करे ; और
 - (घ) जब विनिर्मित माल का विक्रय स्वयं निर्माता द्वारा किया जाता है और यह सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों द्वारा हिमाचल प्रदेश में पुनः विक्रय के लिए क्रय किए गए या अर्जित तैयार माल पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना में—

- (i) “विद्यमान औद्योगिक इकाई” से ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जो विद्यमान थी, 1-4-1991 से 30-9-96 की अवधि के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन में आई हों और जो हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 के अधीन व्याहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई थी, जो इस अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्थान द्वारा 1-10-1996 को या उसके पश्चात् ग्रहण और विक्रय की जाती है ;
- (ii) “नई औद्योगिक इकाई” से ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जो हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 के अधीन व्याहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हों और वाणिज्यिक उत्पादन कर रही हो और 1-10-1996 को या इसके पश्चात् इस अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्थान द्वारा विक्रय किया गया और ग्रहण किया गया हो; और

- (iii) अभिव्यक्ति "औद्योगिक ब्लॉक" से 1-10-1992 के राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश सरकार, आवकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या 1-12/73-ई. एण्ड टी.-III, दिनांक 25-9-1992 में यथा परिभाषित औद्योगिक ब्लॉक अभिप्रेत है।

आदेश द्वारा,
एस0 स0 परमार,
वित्तियुक्त एवं सचिव (आवकारी एवं कराधान)।

[*Authortative English Text of this Department Notification No.EXN-F(13)1/96 (i) dated 27-1-1997 as required under clause (3) of Article 343 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th January, 1997

No. EXN-F (13)1/96 (i).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No.24 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to levy sales tax @1 % and also to grant exemption from the payment of the remaining part of the sales tax leviable under section 6 of the aforesaid Act in respect of goods manufactured and sold by the (i) existing industrial units; and (ii) new industrial units located in any category of Industrial Block, 'A', 'B' and 'C' (other than the Industrial Units specified in the negative list notified *vide* this Department Notification No.1-12/73-E&T-III dated 25-9-1992 and published in Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 1-10-1992 and as amended *vide* Himachal Pradesh Government, Excise and Taxation Department Notification No.EX N-F (13)1/96 (vi) Dated 27-1-1997 which have been taken over on or after 1-10-1996 by the Himachal Pradesh Financial Corporation or the Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation or any Scheduled Commercial Bank in Himachal Pradesh, as the case may be and subsequently sold to new management/promoters/company (whose promoters/directors/management are all new), for a period of three years (36 months) from the date of commencement of commercial production by the industrial unit concerned subject to the following conditions :—

- (i) that all previous liabilities of the unit so taken over and sold pertaining to the Department of Excise and Taxation have been cleared and a 'No Demand Certificate' to this effect has been obtained from the appropriate Assessing Authority;
- (ii) that the industrial unit will file by 30th April, every year with the appropriate Assessing Authority a Certificate in Form R. M.II prescribed by the Himachal Pradesh Government, Excise and Taxation Department *vide* Notification No.1-12/73-E&T-III dated 7-2-1992 published in Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) on 12-2-1992 issued by the authority specified therein;
- (iii) that the benefit of concessional rate of sales tax @1 % will be available only to these industrial units which :—

- (a) are registered with the appropriate Assessing Authority as a dealer, under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No.24 of 1968), after such industrial unit was taken over and sold;

- (b) comply with all the provisions of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968), the rules framed and the notifications issued thereunder;
- (c) submit a 'No Demand Certificate from the Director of Industries, Himachal Pradesh or the General Manager, District Industries Centre of the Department of Industries in respect of any dues payable to the Department of Industries pertaining to the unit purchased; and
- (d) manufacture the goods themselves and sold the same and it shall not be open ~~for~~ finished goods purchased or acquired by concerned industrial units for resale in Himachal Pradesh.

Explanation.—In this notification:—

- (i) "existing industrial unit" means an Industrial unit which was in existence, came into commercial production between 1-4-1991 to 30-9-1996 and was registered as a dealer under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, which was taken over and sold by any of the financial institutions, referred to in this notification, on or after 1-10-1996;
- (ii) "new industrial unit" means an industrial unit which comes into commercial production, has been registered as a dealer under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, and which is taken over and sold by any of the financial institutions, referred to in this notification, on or after 1-10-1996; and
- (iii) the expression "Industrial Block" shall mean the industrial block as defined *vide* Government of Himachal Pradesh, Excise and Taxation Department Notification No. 1-12-/73-E&T-III, dated 25-9-1992 and published in Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 1-10-92.

By order,

S. S. PARMAR,
Financial Commissioner-cum-Secretary.